

खास-खबरे

कच्चे तेल का दाम फिर से सातवें आसमान पर, 110 डॉलर प्रति बैरल हुआ भाव

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच कच्चे तेल का दाम फिर सातवें आसमान पर पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मई के बाद पहली बार ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गई हैं। क्रूड के भाव में यह बढ़ोतरी मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों की वजह से देखने को मिल रही है।अंतरराष्ट्रीय बाजार में शनिवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव 3.94 डॉलर यानी 3.72 फीसदी उछलकर 109.9 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया। मई के बाद पहली बार ब्रेंट ऑयल का रेट इस स्तर पर पहुंचा है। वहीं, कारोबार के अंत में डब्ल्यूटीआई (वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट) 3.44 डॉलर यानी 3.51 फीसदी की तेजी के साथ 101.4 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ है। अमेरिकी सरकार ने रूस और ईरान से सबसे अधिक तेल और गैस खरीदने वाले पांच देशों पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने से राहत दी है।

एसबीआई को लगातार दूसरे साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का पुरस्कार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) को न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका से लगातार दूसरे साल ‘विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026’ का पुरस्कार मिला है। एसबीआई ने शनिवार को ‘एक्स’ पर जारी एक पोस्ट में बताया कि स्टेट बैंक को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने लगातार दूसरे वर्ष ‘विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026’ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बैंक को ये पुरस्कार थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वार्षिक बैठक से इतर आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया। देश के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक एसबीआई ने बताया कि यह सम्मान डिजिटल नवाचार, बेहतर सेवा और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता के जरिये ग्राहक-केंद्रित बैंकिंग में वैश्विक मानक स्थापित करने की उसकी निरंतर सफलता को दर्शाता है।

इस अवसर पर एसबीआई के चेयरमैन सी एस शेठ्टी ने कहा कि बैंक में जारी बदलावों, खासकर डिजिटल क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का उद्देश्य बड़े पैमाने पर लोगों को भरोसेमंद डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि डिजिटल क्षमताओं में सुधार से बैंक अधिक लोगों तक पहुंचने और उन्हें तेजी से सेवाएं देने में सक्षम हुआ है। शेठ्टी ने आगे कहा बैंक के कर्मचारी यह सुनिश्चित करते हैं कि बैंकिंग सेवाएं व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप, सुलभ और भरोसेमंद बनी रहें। इस दौरान बैंक ने नया योनो मंच शुरू किया और योनो पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 10 करोड़ के पार पहुंच गई है।

एसबीआई के चेयरमैन ने कहा कि इसके अलावा बैंक ने कृत्रिम मेधा (एआई) आधारित ग्राहक सेवाएं और व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप डिजिटल सुविधाओं की शुरु की है। एसबीआई ने देशभर में 300 से भी अधिक नई शाखाएं खोलकर अपनी पहुंच का भी विस्तार किया है।

एफएसएसएआई ने सूर्या फूड एंड एग्रो, डोडला डेयरी के खिलाफ की कार्रवाई

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के लिए प्रियागोल्ड बिस्कुट बनाने में पशुओं के चारे वाले चोकर का उपयोग करने के लिए सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने शनिवार को एकस पोस्ट में बताया कि खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन के लिए सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड, डोडला डेयरी और यूईआईआर ऑर्गेनिक फूड्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई। नियामक ने इन तीनों कंपनियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा नियमों के गंभीर उल्लंघन को लेकर अभियोजन की कार्रवाई शुरू किए जाने की जानकारी दी। एफएसएसएआई के अनुसार प्रियागोल्ड बिस्कुट बेचने वाली भारतीय एफएमसीजी कंपनी सूर्या फूड एंड एग्रो के संयंत्र का निरीक्षण उपभोक्ताओं की शिकायत के बाद किया गया। कंपनी के निरीक्षकों ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी कई गंभीर खामियां सामने आईं। एफएसएसएआई ने कहा, “पशु चारे के लिए बने चोकर का इस्तेमाल प्रियागोल्ड बिस्कुट बनाने में फाइबर के स्रोत के तौर पर कच्चे माल के रूप में किया जा रहा था। यह चोकर ईंसानों के खाने में लिफा नहीं था।”नियामक ने कहा कि चोकर से भरी बोरियों पर स्पष्ट रूप से अंकित था कि यह सामग्री पशु चारे के लिए है।

स्पेशल खबर

स्टारलिनक भारत में इंटरनेट सेवा शुरू करने को तैयार...

कंपनी बोली- पांच वर्षों से भारतीय नियामकों के साथ कर रहे काम

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिनक ने भारत में तीव्र गति वाली उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी होने की जानकारी दी है। कंपनी ने कहा कि वह पिछले पांच वर्षों से भारतीय नियामकों, उद्योग जगत और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम कर रही है। हालांकि, सेवा शुरू करने के लिए आवश्यक सरकारी मंजूरीयों का इंतजार है।

स्टारलिनक ने सामाजिक माध्यम पर जारी बयान में बताया कि भारतीय उपयोगकर्ताओं का आंकड़ा सुरक्षित रखने के लिए देश में आवश्यक द्वार केंद्र और



विशेष प्रणालियां तैयार की गई हैं। कंपनी का दावा है कि अनुमति मिलते ही वह ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा शुरू कर सकती है।

इससे पहले मस्क ने भारत में अनुमति मिलने में देरी को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ भारतीय कारोबारी स्टारलिनक

आठ साल में 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

निजी निवेश, त्वरित मंजूरी और बाजार की मांग से बड़ेगा अंतरिक्ष उद्योग:जितेंद्र सिंह

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले सात से आठ वर्षों में बढ़कर 40 से 45 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती है। वर्तमान में इसका आकार लगभग नौ अरब अमेरिकी डॉलर है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित एक परिचर्चा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी तकनीकी उपलब्धियों से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी अंतरिक्ष कंपनियां विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए।

डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2019-20 में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोलने के बाद महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अब निजी निवेश बढ़ाने, उत्पादों की मांग सुनिश्चित करने और नियामकीय मंजूरीयों की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता है। इससे भारतीय कंपनियां अपने उत्पादों को व्यावसायिक रूप देने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में



सक्षम होंगी। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियों के लिए सरकारी संस्थानों को संभावित ग्राहक के रूप में विकसित करना महत्वपूर्ण है। शुरुआती परियोजनाओं और प्रौद्योगिकी के सफल प्रदर्शन से कंपनियों को निवेश बढ़ाने, उत्पादन क्षमता विकसित करने और आय के स्थायी स्रोत तैयार करने में सहायता मिल सकती है। मंत्री ने कारोबार की लागत घटाने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और निर्धारित समयसीमा में आवश्यक अनुमतियां देने पर भी जोर दिया। उनके अनुसार, घरेलू क्षमताओं को मजबूत करते हुए

अंतरराष्ट्रीय निवेश और साझेदारियों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ने और नए बाजारों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा।

डॉ. सिंह ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यावहारिक उपयोगों का उल्लेख करते हुए कहा कि उपग्रह संचार, पृथ्वी अवलोकन और भू-स्थानिक तकनीक का इस्तेमाल कृषि, आधारभूत ढांचे की निगरानी, आपदा प्रबंधन और रक्षा जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। परियोजनाओं की निगरानी और विकास कार्यों की

छह माह तक के शिशुओं के खाद्य उत्पादों में अतिरिक्त शर्करा पर प्रतिबंध का प्रस्ताव

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: शिशुओं के पोषण संबंधी सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने शिशु पोषण से संबंधित विनियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसमें छह माह तक की आयु के शिशुओं के लिए निर्धारित खाद्य उत्पादों में सुक्रोज और फ्रक्टोज मिलाने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य शिशुओं की आयु के अनुरूप पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना और जीवन के शुरुआती चरण में अतिरिक्त शर्करा के सेवन से बचना है।

भारत के राजपत्र में 16 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य पदार्थ) संशोधन विनियम, 2026 के मसौदे के माध्यम से मौजूदा नियामक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है। इसके तहत प्रस्ताव है कि छह माह तक की आयु के शिशुओं के लिए निर्धारित उत्पादों में सुक्रोज और फ्रक्टोज नहीं मिलाए जाएंगे। वर्तमान विनियमों में जन्म से लेकर 24 माह तक के बच्चों के लिए निर्धारित विभिन्न श्रेणियों के शिशु पोषण उत्पादों की पोषण संरचना, गुणवत्ता और सुरक्षा के मानक तय हैं। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, लैक्टोज और ग्लूकोज पॉलिमर कार्बोहाइड्रेट के पसंदीदा स्रोत हैं। सुक्रोज और फ्रक्टोज को निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत तभी मिलाने की अनुमति है, जब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के रूप में उनकी आवश्यकता हो।

जीवन के पहले छह माह शिशुओं की



►►खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने विनियमों में संशोधन का मसौदा किया जारी

►►60 दिनों में मांगे सुझाव और आपत्तियां

स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रस्तावित प्रतिबंध का उद्देश्य इस अवधि में अतिरिक्त शर्करा के सेवन से जुड़े आहार संबंधी जोखिमों, विशेषकर बचपन में मोटापे और उससे संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के प्रयासों को समर्थन देना है। यह पहल छह माह तक केवल स्तनपान को बढ़ावा देने संबंधी जनस्वास्थ्य सिफारिशों के अनुरूप भी है। प्राधिकरण ने संशोधन का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। हितधारक राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराए जाने की तिथि से 60 दिनों के भीतर अपनी आपत्तियां और सुझाव दे सकते हैं। निर्धारित अवधि में प्राप्त अभ्यावेदनों पर संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले विचार किया जाएगा।

दो नए किफायती प्रोजेक्टर पेश 6,999 रुपये से शुरू कीमत

120 इंच तक बड़ी स्क्रीन पर देख सकेंगे सामग्री

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: घर पर बड़ी स्क्रीन पर फिल्में और अन्य सामग्री देखने के इच्छुक लोगों के लिए जस्ट कोर्सिका ने भारत में दो नए किफायती प्रोजेक्टर पेश किए हैं। इन मॉडलों के नाम जेसी स्टूडियोक्स और जेसी स्टूडियोक्स प्रो हैं। इनकी शुरुआती कीमत 6,999 रुपये रखी गई है। कंपनी के अनुसार, दोनों उपकरण 4के सामग्री का समर्थन करते हैं और घर में मनोरंजन के लिए तैयार किए गए हैं।

दोनों प्रोजेक्टर की कीमत

जेसी स्टुडियोक्स की कीमत

6,999 रुपये है, जबकि जेसी स्टुडियोक्स प्रो को 10,999 रुपये में पेश किया गया है। इन्हें कंपनी के आधिकारिक बिक्री मंच के अलावा अमेज़न इंडिया, फ्लिपकार्ट और अन्य मंचों से खरीदा जा सकता है। दोनों उपकरणों में नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब का समर्थन उपलब्ध है।

पहले मॉडल की विशेषताएं

जेसी स्टुडियोक्स को रोजमर्रा के घरेलू मनोरंजन की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें उच्च स्पष्टता वाले दृश्य दिखाने की सुविधा, बेतार संपर्क

दूसरी तिमाही में ब्याज आय 9.7 प्रतिशत बढ़ी, फंसे कर्ज में सुधार और जमा राशि में 18.8 प्रतिशत की वृद्धि

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: एचडीएफसी बैंक ने चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही के वित्तीय परिणाम शनिवार को घोषित किए। बैंक का शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 4.7 प्रतिशत बढ़कर 19,510 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में शुद्ध ब्याज आय में भी 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यह बढ़कर 34,619 करोड़ रुपये रही।

बैंक की वित्तीय स्थिति में सुधार के संकेत मिले हैं। 30 सितंबर 2026 तक सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात घटकर 1.11 प्रतिशत रह गया, जो जुन तिमाही में 1.17 प्रतिशत और पिछले वर्ष सितंबर में 1.24 प्रतिशत था। शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात 0.37 प्रतिशत दर्ज किया गया।

बैंक का सकल ऋण वितरण सालाना आधार पर 16.3 प्रतिशत बढ़कर 32,19,500 करोड़ रुपये हो गया। छोटे और मध्यम उद्यमों को दिए गए ऋण में 23.5 प्रतिशत, खुदरा ऋण में 11.7 प्रतिशत और कंपनियों को दिए जाने वाले थोक ऋण में 16.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बैंक की कुल जमा राशि 18.8 प्रतिशत बढ़कर 33,27,400 करोड़ रुपये पर पहुंच गई। चालू और

एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 4.7 प्रतिशत बढ़कर 19,510 करोड़



बचत खातों में जमा राशि में 10.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह कुल जमा राशि का 31.6 प्रतिशत रही, जबकि सावधि जमा में 22.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तिमाही में बैंक का शुद्ध

राजस्व 48,450 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 45,900 करोड़ रुपये था। परिचालन व्यय बढ़कर 18,970 करोड़ रुपये हो गया। बैंक का लागत-आय अनुपात 39.1

प्रतिशत दर्ज किया गया। सितंबर के अंत में पूंजी पर्याप्तता अनुपात 18.9 प्रतिशत रहा।

इस बीच, बैंक के उप प्रबंध निदेशक कैजाद भरूचा ने तीन दशक से अधिक समय तक सेवा देने के बाद इस्तीफा दे दिया है। वह 31 दिसंबर 2026 को पद छोड़ेंगे। बैंक ने लिली वड्डेरा को तीन वर्ष के लिए फिर से स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। शुक्रवार को बैंक का शेयर 728.85 रुपये पर बंद हुआ। वर्ष 2026 में अब तक इसके मूल्य में लगभग 26.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

आईडीबीआई में सरकारी हिस्सेदारी घटाने पर कोई कानूनी रोक नहीं: केंद्र

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाने से संबंधित विधायी घटनाक्रमों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार ने कहा कि वर्ष 2003 के आईडीबीआई निरसन अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो उसे बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम करने या पूरी तरह समाप्त करने से रोकता हो। सरकार के अनुसार, केंद्रीय बजट 2003 पर चर्चा और आईडीबीआई निरसन अधिनियम पर संसदीय बहस के दौरान सरकारी हिस्सेदारी में कमी सीमित करने के उद्देश्य से एक संशोधन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे अंततः अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए यह संशोधन अधिनियमित कानून का हिस्सा नहीं बना। इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने

ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामलों में 17 दिसंबर 2018 को फैसला सुनाया था। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि संसदीय बहस के दौरान दिए गए वक्तव्य अधिनियमित कानून का स्थान नहीं ले सकते। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून में सरकार की हिस्सेदारी घटाने या पूरी तरह समाप्त करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार ने अपने स्पष्टीकरण में केंद्रीय बजट के पुराने प्रावधानों का भी उल्लेख किया। वर्ष 2016-17 के बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आईडीबीआई बैंक में सरकारी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से कम करने के विकल्प पर विचार करने की बात कही थी।

रेल और सड़क नेटवर्क से कश्मीर में विकास बढ़ा चिनाब पुल, वंदे भारत रेल सेवा और सुरंग परियोजनाओं से आवागमन, ट्यापार तथा पर्यटन को बढ़ावा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद रेल, सड़क और हवाई संपर्क के बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल संपर्क परियोजना ने कश्मीर घाटी को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे मेहराबदार पुल और वंदे भारत रेल सेवा इस परियोजना की प्रमुख उपलब्धियां हैं। बेहतर संपर्क से क्षेत्र के व्यापार, पर्यटन और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।

करीब 43,780 करोड़ रुपये की लागत से बनी 272 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना में 36 सुरंगों और 943 पुल शामिल हैं। इसकी सुरंगों की कुल लंबाई 119 किलोमीटर है। परियोजना के निर्माण से रोजगार के पांच करोड़ से अधिक मानव-दिवस सृजित हुए। जून



2025 में शुरू हुई वंदे भारत रेल सेवा का अप्रैल 2026 में जम्मू तबी तक विस्तार किया गया। अब जम्मू से श्रीनगर की यात्रा पांच घंटे से कम समय में पूरी की जा सकती है। रियासी जिले में स्थित चिनाब रेल पुल 1,315 मीटर लंबा है। इसका मेहराब 467 मीटर लंबा और नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है। वहीं, अंजी खड्ड पुल देश का पहला केबल आधारित रेलवे पुल है। वर्ष 2024 में शुरू हुई 12.77 किलोमीटर लंबी टी-50 रेल सुरंग भी इस संपर्क व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए सोनमर्ग और जोजिला सुरंगों सहित कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। जनवरी 2025 में शुरू हुई 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग से पूरे वर्ष आवागमन में सहायता मिलने की उम्मीद है।

नवंबर में बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, महंगाई बढ़ने की आशंका

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: देश में नवंबर के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। आर्थिक शोध संस्था ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की प्रमुख अर्थशास्त्री एलेक्जेंड्रा हरमन प्रसाद ने यह संभावना जताई है। उनके अनुसार, अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले ईंधन की कीमतों में बदलाव के लिए नवंबर का महीना महत्वपूर्ण हो सकता है। हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर में पेट्रोल और डीजल के दाम में संभावित वृद्धि इस वर्ष मई में हुई बढ़ोतरी की तुलना में लगभग आधी हो सकती है। मई में मध्य पूर्व में तनाव के कारण ईंधन की खुदरा कीमतों में करीब 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। अब संभावित बढ़ोतरी का असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अनुमान के मुताबिक, यदि नवंबर में ईंधन की कीमतें बढ़ती हैं, तो अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में खुदरा महंगाई दर 6.2 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। वर्ष 2027 की पहली तिमाही में इसके 6.5 प्रतिशत तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के दो से छह प्रतिशत के निर्धारित महंगाई लक्ष्य से अधिक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस महीने की मौद्रिक नीति समीक्षा में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए महंगाई दर छह प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था।